IAS GS World PCS

Committed To Excellence

DAILY CURRENT AFFAIRS ANALYSIS

(Pre+Mains) with MCQ

28 MAY 2026

FOR PDF DOWNLOAD
GS WORLD LEARNING APP

Today Important

Current Affairs Analysis

28th May 2026

1. भारत ने विकसित की क्रांतिकारी CLEAR तकनीक — कैंसर अनुसंधान में नई उम्मीद

एक ही जैविक नमूने में सैकड़ों प्रोटीन मैप करने में सक्षम यह नई इमेजिंग प्रणाली, पारंपरिक सीमाओं को तोड़ती है।

28 मई, 2026 | बेंगलुरु | JNCASR

भारत के वैज्ञानिकों ने प्रोटीन इमेजिंग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (JNCASR), बेंगलुरु — जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है — के शोधकर्ताओं ने एक अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जिसे **CLEAR** नाम दिया गया है।

- **पूर्ण नाम:** Cleavable Light-Erased Antibody Reporter
- **विकसित किया:** JNCASR, बेंगलुरु
- **मंत्रालय:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- **प्रमुख उपयोग:** कैंसर एवं तंत्रिका रोग अनुसंधान

CLEAR तकनीक क्या है?

CLEAR एक मल्टीप्लेक्स्ड स्थानिक प्रोटीन इमेजिंग प्लेटफॉर्म है। पारंपरिक इमेजिंग में अलग-अलग प्रोटीन के लिए अलग-अलग रंगीन फ्लोरोसेंट टैग चाहिए होते हैं और माइक्रोस्कोप एक बार में केवल कुछ रंगों को ही पहचान सकता है। CLEAR इस सीमा को एक चक्रीय "मिटाओ और फिर लिखो" प्रक्रिया से पार कर लेती है — ठीक जैसे एक ही चॉकबोर्ड पर बार-बार नई जानकारी लिखते रहना।

यह काम कैसे करती है?

1. **लक्षित लेबलिंग:** CLEAR प्रोब — एंटीबॉडी जिनसे एक प्रकाश-संवेदनशील रासायनिक कड़ी के ज़रिए फ्लोरोसेंट टैग जुड़ा होता है — ऊतक नमूने में विशेष प्रोटीनों को चिह्नित करते हैं।
2. **प्रथम इमेजिंग:** माइक्रोस्कोप के नीचे नमूने की छवि ली जाती है।
3. **फोटोलिटिक इरेजिंग:** 365 nm UV LED प्रकाश की एक हल्की पल्स रासायनिक बंध को तोड़ देती है और फ्लोरोसेंस संकेत मिट जाता है — बिना ऊतक को नुकसान पहुंचाए।
4. **चक्रीय पुनर्लेखन:** नए प्रोटीनों को उसी स्पेक्ट्रल विंडो में लेबल कर इमेज किया जाता है। यह चक्र बार-बार दोहराया जाता है।

इस तकनीक की खास बातें

- **हाई-प्लेक्स मल्टीप्लेक्सिंग:** एक ही नमूने में सैकड़ों प्रोटीन को विज़ुअलाइज़ करना संभव।
- **जीवित कोशिका अनुकूल:** पुरानी विधियों में कठोर रसायनों या ताप का उपयोग होता था जो ऊतक को नष्ट कर सकता था। CLEAR की प्रकाश-आधारित प्रक्रिया नाज़ुक जैविक नमूनों को सुरक्षित रखती है।
- **उच्च स्थानिक रेज़ॉल्यूशन:** कोशिकाओं के बीच संचार और ऊतक के सूक्ष्म वातावरण को समझने के लिए प्रोटीन की सटीक स्थिति का मानचित्र तैयार होता है।
- **तेज़ और किफ़ायती:** केवल एक फ्लोरोसेंट चैनल बार-बार उपयोग होने से जटिल मल्टी-लेज़र सेटअप की ज़रूरत नहीं रहती।

महत्व

CLEAR तकनीक का सर्वाधिक प्रभाव कैंसर और तंत्रिका संबंधी विकारों के अनुसंधान में पड़ेगा। जब वैज्ञानिक एक ही ट्यूमर ऊतक में एक साथ दर्जनों प्रोटीन मार्करों को देख सकेंगे, तो रोग के सटीक तंत्र को समझना और व्यक्तिगत उपचार विकसित करना बहुत आसान हो जाएगा। यह भारत के लिए जैव-चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक गर्व का क्षण है।

स्रोत: DD News | JNCASR, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

Question based on the Topic	
Mains question	**Prelims Question**
Question: CLEAR Technology पारंपरिक multiplexed protein imaging की सीमाओं को किस प्रकार दूर करती है? कैंसर और तंत्रिका संबंधी रोगों के उपचार में इसकी संभावित भूमिका का परीक्षण कीजिए।	**1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:** 1. CLEAR technology एक multiplexed spatial protein imaging platform है जिसे JNCASR द्वारा विकसित किया गया है। 2. यह fluorescence signal को मिटाने के लिए 365 nm UV LED light का उपयोग करती है। 3. JNCASR विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है। 4. CLEAR technology जीवित कोशिकाओं के साथ असंगत है क्योंकि यह कठोर रसायनों का उपयोग करती है। **उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?** (a) केवल एक (b) केवल दो (c) केवल तीन (d) सभी चार ***उत्तर: (b) केवल दो (कथन 1 और 2 सही हैं। कथन 3 गलत है — JNCASR एक Statutory Body नहीं बल्कि Autonomous Institute है। कथन 4 गलत है — CLEAR जीवित कोशिकाओं के साथ पूरी तरह compatible है।)***

2. Memflation: AI की भूख से महंगे हुए Memory Chips — जानिए क्या है यह नया संकट

वैश्विक semiconductor उद्योग $1.3 trillion के पार, लेकिन पारंपरिक computing के लिए बढ़ती कीमतें बनी मुसीबत

28 मई, 2026 | अर्थव्यवस्था

दुनिया की सबसे बड़ी technology research firm Gartner के विश्लेषकों ने एक नया शब्द गढ़ा है — **Memflation**। यह शब्द उस तेज़ और structural price inflation को describe करता है जो semiconductor बाज़ार में, विशेष रूप से data storage और memory components में, देखी जा रही है। सरल भाषा में कहें तो — AI infrastructure की अंधाधुंध मांग ने memory chips की इतनी बड़ी खपत शुरू कर दी है कि पारंपरिक computing के लिए supply कम पड़ रही है और कीमतें आसमान छू रही हैं।

वैश्विक semiconductor बाज़ार में ऐतिहासिक उछाल

इस वर्ष वैश्विक semiconductor revenues $1.3 trillion का आंकड़ा पार कर सकती है — जो 2025 की तुलना में 64% की वृद्धि है। 2027 तक यह आंकड़ा $1.6 trillion तक पहुंचने का अनुमान है। इस उछाल का सबसे बड़ा कारण AI infrastructure में हो रहा भारी निवेश है, जिसने Nvidia को semiconductor revenues में Samsung Electronics को भी पीछे छोड़ने पर मजबूर कर दिया है।

Memflation के मुख्य कारण

- **AI Infrastructure Boom:** Amazon, Google, Microsoft जैसे hyperscalers और cloud companies AI infrastructure पर अभूतपूर्व खर्च कर रही हैं। इससे memory resources का बड़ा हिस्सा AI की ओर मुड़ गया है और पारंपरिक computing बाज़ार के लिए supply सिकुड़ती जा रही है।
- **Production Shift:** Micron Technology जैसी बड़ी chip निर्माता कंपनियां अधिक मुनाफे वाले AI GPUs और enterprise memory को consumer components पर प्राथमिकता दे रही हैं। इससे आम उपभोक्ता और छोटे व्यवसायों के लिए chips की उपलब्धता कम हो रही है।
- **Pre-Emptive Bulk Buying:** अमेरिकी tariffs और भविष्य में कीमतें और बढ़ने के डर से कंपनियों ने 2025–26 में chips की बड़े पैमाने पर stockpiling शुरू कर दी। इससे available inventory तेज़ी से घट गई और कृत्रिम कमी पैदा हो गई।

कितनी बढ़ेंगी कीमतें?

Industry estimates के अनुसार आने वाले समय में memory chip की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है —

DRAM prices में लगभग **125%** की वृद्धि का अनुमान है, जबकि NAND flash prices में **243%** तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह वृद्धि 2028 तक supply chains को प्रभावित करती रहेगी।

Memflation के प्रभाव

- **Non-AI Technology पर असर:** बढ़ती memory costs की वजह से enterprise IT upgrades धीमी पड़ रही हैं। पारंपरिक digital infrastructure की deployment में भारी देरी हो रही है।

- **Supply Chain Disruption:** Semiconductor shortages और logistics bottlenecks ने वैश्विक hardware markets में shipment delays की लहर पैदा कर दी है।
- **आम उपभोक्ता पर बोझ:** Laptop, server और enterprise hardware निर्माता बढ़ी हुई semiconductor लागत सीधे ग्राहकों पर डाल रहे हैं। यानी आने वाले समय में आपका नया laptop या computer पहले से महंगा हो सकता है।
- **Long-Term Contracts का जोखिम:** Gartner के विश्लेषकों ने CIOs को सलाह दी है कि volatile pricing के माहौल में महंगे multi-year semiconductor supply agreements से बचें, क्योंकि बाज़ार की दिशा अभी अनिश्चित है।

निष्कर्ष

Memflation एक ऐसा संकट है जो AI की सफलता की कीमत पर पारंपरिक technology sector को चुका रहा है। जब तक semiconductor fabrication capacity में बड़े पैमाने पर विस्तार नहीं होता, यह असंतुलन बना रहेगा। भारत जैसे देशों के लिए, जो अपनी semiconductor manufacturing क्षमता विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, यह संकट एक अवसर भी है — अपनी chip supply chain को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाने का।

स्रोत: The Hindu | Gartner Research

Question based on the Topic	
Mains question	**Prelims Question**
Question: 'Memflation' की अवधारणा क्या है? AI-driven demand के संदर्भ में भारत के Semiconductor Mission के समक्ष उपस्थित चुनौतियों और अवसरों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।	**2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:** 1. 'Memflation' शब्द Gartner analysts द्वारा गढ़ा गया है। 2. इसके अनुसार DRAM prices में लगभग 243% और NAND Flash prices में लगभग 125% की वृद्धि का अनुमान है। 3. AI demand के कारण Nvidia ने semiconductor revenues में Samsung Electronics को पीछे छोड़ दिया है। 4. वैश्विक semiconductor revenue 2026 में $1.3 trillion को पार करने का अनुमान है जो 2025 की तुलना में 64% अधिक है। **उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?** (a) केवल एक (b) केवल दो (c) केवल तीन (d) सभी चार **उत्तर: (c) केवल तीन *(कथन 2 गलत है — DRAM में ~125% और NAND Flash में ~243% वृद्धि का अनुमान है, न कि उल्टा। कथन 1, 3 और 4 सही हैं।)***

3. PM-WANI: सार्वजनिक Wi-Fi को नया रूप — आम नागरिकों के लिए बड़ा बदलाव

डिजिटल भारत की राह में एक और कदम — अब चाय की दुकान से लेकर बस स्टैंड तक मिलेगा सुरक्षित इंटरनेट

28 मई, 2026 | सरकारी योजना | DoT, संचार मंत्रालय

भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने PM-WANI — यानी **Prime Minister's Wi-Fi Access Network Interface** — framework के अंतर्गत एक श्रृंखला of citizen-friendly सुधार लागू किए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य सार्वजनिक Wi-Fi को और अधिक सरल, सुरक्षित और सुलभ बनाना है — चाहे उपयोगकर्ता किसी रेलवे स्टेशन पर हो, बाज़ार में हो, या किसी छोटे से कस्बे में।

PM-WANI क्या है?

PM-WANI एक distributed, architecture-driven digital public infrastructure framework है जिसे भारत भर में unlicenced सार्वजनिक Wi-Fi networks के माध्यम से broadband internet का प्रसार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इसे **9 दिसंबर 2020** को Union Cabinet द्वारा मंजूरी दी गई थी। इसका Nodal Department, Department of Telecommunications (DoT) है, जो संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

इस योजना का मूल उद्देश्य बेहद सरल है — छोटी दुकानें, चाय की दुकानें, और मोहल्ले की establishments को last-mile internet service providers बनाकर इंटरनेट की पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना।

PM-WANI Ecosystem के चार स्तंभ

- **Public Data Office (PDO):** यह last-mile service delivery node है। PDO स्थानीय telecom या ISP से commercial internet bandwidth खरीदते हैं और PM-WANI compliant Wi-Fi hotspots स्थापित व संचालित करते हैं। कोई भी छोटा व्यापारी PDO बन सकता है।
- **Public Data Office Aggregator (PDOA):** यह backend central management layer के रूप में कार्य करता है। PDOA विभिन्न PDOs को एकत्रित करता है और उन्हें user authorization, network security, तथा financial accounting जैसी तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है।
- **App Provider:** ये user-facing mobile applications विकसित और maintain करते हैं। इन apps के माध्यम से उपयोगकर्ता का registration होता है, authentication होती है और आसपास के PM-WANI hotspots discover किए जाते हैं।
- **Central Registry:** यह सभी certified App Providers, PDOAs और PDOs की master directory बनाए रखता है। इसे वर्तमान में Centre for Development of Telematics (C-DoT) द्वारा manage किया जाता है।

PM-WANI की खास संरचनागत विशेषताएं

- **Zero Licensing और Zero Fee:** Ease of doing business को बढ़ावा देने के लिए last-mile PDOs के लिए कोई license नहीं, कोई registration नहीं, और DoT को शून्य शुल्क देना होता है।

- **Frictionless Aggregator Onboarding:** Backend PDOAs भी licensing requirements से मुक्त हैं। उन्हें केवल एक निःशुल्क registration process पूरी करनी होती है, जो application filing के 7 कार्य दिवसों के भीतर पूरी हो जाती है।
- **Open Interoperability:** एक बार किसी approved App Provider से authenticate हुआ उपयोगकर्ता बिना बार-बार registration किए देश के किसी भी PDO hotspot पर सार्वजनिक Wi-Fi broadband access कर सकता है।

2026 के नए सुधार: नागरिकों को क्या मिला?

- **QR Code से Laptop Connection:** अब उपयोगकर्ताओं को laptop पर manually login करने की परेशानी नहीं होगी। Authenticated smartphone app से landing page पर एक dynamic QR code scan करके laptop को तुरंत secure public network से जोड़ा जा सकता है।
- **Flexible Sachet Plans:** Hotspot operators को अब 15, 30 और 60 मिनट की अत्यंत किफायती short-duration validity plans प्रदान करने की सलाह दी गई है। ये plans transit hubs, बाज़ारों और रेलवे स्टेशनों पर आने-जाने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं।
- **Standardized Hotspot Identification (SSIDs):** अब network names (SSIDs) में PMWANI branding को अनिवार्य रूप से शामिल करने का mandate है। इससे नागरिक आसानी से authentic, सुरक्षित सार्वजनिक connections को नकली या malicious networks से अलग पहचान सकेंगे।

महत्व और संभावना

PM-WANI योजना डिजिटल भारत की उस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जहाँ इंटरनेट केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहे। जब एक चायवाला भी PDO बनकर अपने इलाके में Wi-Fi सेवा दे सकता है, तो यह डिजिटल समावेश का एक अभूतपूर्व मॉडल बन जाता है।

2026 के ये सुधार — QR code से laptop जोड़ना, sachet plans, और standardized SSIDs — PM-WANI को न केवल तकनीकी रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि इसे आम नागरिक के लिए वास्तव में उपयोगी और भरोसेमंद बनाते हैं।

स्रोत: News on Air | DoT, Ministry of Communications

Question based on the Topic

Mains question	Prelims Question
Question: PM-WANI framework की चार-स्तरीय संरचना की व्याख्या कीजिए। 2026 के हालिया सुधारों के संदर्भ में इसकी उपलब्धियों और सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए।	**3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:** 1. PM-WANI को 9 दिसंबर 2020 को Union Cabinet द्वारा अनुमोदित किया गया था। 2. PM-WANI framework के Central Registry को वर्तमान में C-DoT (Centre for Development of Telematics) द्वारा manage किया जाता है। 3. Public Data Office (PDO) को DoT से license प्राप्त करना अनिवार्य है। 4. PM-WANI के अंतर्गत एक approved App Provider से authenticate हुआ उपयोगकर्ता देश के किसी भी PDO hotspot पर Wi-Fi access कर सकता है। **उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?** (a) केवल एक (b) केवल दो (c) केवल तीन (d) सभी चार **उत्तर: (c) केवल तीन *(कथन 3 गलत है — PDOs को कोई license नहीं लेना होता और कोई fee नहीं देनी होती। कथन 1, 2 और 4 सही हैं।)***

4. Quad Critical Minerals Initiative Framework: चीन पर निर्भरता खत्म करने की बड़ी रणनीति

नई दिल्ली में 11वीं Quad विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बनाया ऐतिहासिक खनिज सुरक्षा ढांचा

28 मई, 2026 | अंतर्राष्ट्रीय संगठन | Quad

नई दिल्ली में आयोजित 11वीं Quad विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया — Quad के चारों सदस्य देशों — ने मिलकर **Quad Critical Minerals Initiative Framework** का अनावरण किया। इसके साथ ही एक अलग द्विपक्षीय India-US mineral pact भी सामने आया। यह framework Indo-Pacific क्षेत्र में Quad के बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक महत्व का स्पष्ट संकेत है।

यह Framework क्या है?

Quad Critical Minerals Initiative Framework एक बहुपक्षीय रणनीतिक आर्थिक और supply-chain insulation pact है। यह Quad के उस बदलाव का हिस्सा है जिसमें यह गठबंधन धीरे-धीरे एक advanced infrastructure development, resource security और आर्थिक समन्वय के मंच के रूप में विकसित हो रहा है।

इसका प्राथमिक उद्देश्य critical minerals और rare earth elements के लिए स्थिर, resilient और अत्यधिक diversified वैश्विक supply routes स्थापित करना है — और सीधे तौर पर China-dominated supply corridors द्वारा थोपी जाने वाली export restrictions और अचानक आपूर्ति कटौती से होने वाली कमज़ोरियों को दूर करना है।

Framework की प्रमुख विशेषताएं

- **$20 Billion की विशाल पूंजी जुटाना:** यह framework public funding, soft loans और private investments के माध्यम से लगभग $20 billion mobilize करने की योजना रखता है ताकि critical mineral supply chains को मज़बूत किया जा सके।
- **Geographic और Ownership नियम:** Supported projects केवल Quad देशों के भीतर स्थित होने चाहिए और उन्हें सदस्य देशों की कंपनियों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए — ताकि strategic control सुनिश्चित रहे।
- **End-to-End Supply Chain Coverage:** यह framework पूरी mineral chain को support करता है — mining और processing से लेकर refining, manufacturing inputs और recycling systems तक।
- **Regulatory Harmonization:** Quad सदस्य customs rules, environmental norms और legal standards को आपस में align करेंगे ताकि cross-border mineral trade और investment आसान हो सके।
- **E-Waste Circular Economy:** यह पहल advanced recycling methods के माध्यम से e-waste और industrial scrap से rare earth elements और strategic metals की recovery को बढ़ावा देती है।
- **National Security Safeguards:** सदस्य देश संयुक्त रूप से export controls और monitoring systems विकसित करेंगे ताकि strategic minerals शत्रुतापूर्ण actors तक न पहुंच सकें।

यह Framework क्यों महत्वपूर्ण है?

- **चीन पर निर्भरता में कमी:** दुनिया के rare earth exports में चीन का दबदबा किसी से छुपा नहीं है। यह framework वैश्विक mineral supply chains को diversify कर उस निर्भरता को कम करने की दिशा में एक ठोस कदम है।
- **भारत-अमेरिका सहयोग को बल:** यह Pax Silica जैसी initiatives का पूरक है — जिसमें अमेरिका की financing strength और भारत की बढ़ती mineral processing capacity का संयोजन होता है।
- **भविष्य की तकनीकों की सुरक्षा:** Critical minerals EV batteries, semiconductors, solar panels और defence systems के लिए अनिवार्य हैं। इनकी supply security आज के भू-राजनीतिक परिदृश्य में रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है।

भारत के लिए विशेष महत्व

भारत के लिए यह framework कई कारणों से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहाँ भारत अपने mineral processing sector को विकसित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक ऐसा वैकल्पिक supply corridor बनाने का अवसर मिल रहा है जो China के एकाधिकार को चुनौती दे सके। साथ ही India-US bilateral mineral pact इस बहुपक्षीय framework को और मज़बूत आधार देता है।

EV revolution, semiconductor manufacturing और अपने defence sector को आत्मनिर्भर बनाने की राह पर चल रहे भारत के लिए critical minerals की सुरक्षित और निर्बाध आपूर्ति एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुकी है — और यह framework उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।

स्रोत: The Hindu | 11th Quad Foreign Ministers' Meeting, New Delhi

Question based on the Topic	
Mains question	**Prelims Question**
Question: Quad Critical Minerals Initiative Framework के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए। भारत की critical mineral सुरक्षा और Indo-Pacific रणनीति पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए।	**4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:** 1. Quad Critical Minerals Initiative Framework को 11वीं Quad Foreign Ministers' Meeting में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। 2. यह framework critical minerals की पूरी supply chain — mining से लेकर recycling तक — को support करता है। 3. Supported projects Quad देशों के बाहर भी स्थित हो सकते हैं यदि वे Quad member companies द्वारा संचालित हों। 4. यह framework लगभग $20 billion mobilize करने की योजना रखता है। **उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?** (a) केवल एक (b) केवल दो (c) केवल तीन (d) सभी चार **उत्तर: (c)** केवल तीन *(कथन 3 गलत है — Supported projects केवल Quad देशों के भीतर होने चाहिए। कथन 1, 2 और 4 सही हैं।)*

5. Justice Naolekar Committee: अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव की जांच के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों की व्यापक जांच के लिए बहु-विषयक पैनल का गठन किया

28 मई, 2026 | विविध | गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत भर में असामान्य जनसांख्यिकीय बदलावों से उत्पन्न जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। यह समिति अवैध आव्रजन और असाधारण जनसंख्या परिवर्तनों की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित एक विशेष, बहु-विषयक केंद्रीय पैनल है।

समिति की संरचना

- **अध्यक्ष:** न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर — भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश।
- **प्रमुख सदस्य:**
  भारत के Census Commissioner इस समिति के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और著名 अर्थशास्त्री शमिका रवि भी इस पैनल में शामिल हैं।
- **Member Secretary:** गृह मंत्रालय में Joint Secretary (Foreigners-I)।

समिति के उद्देश्य

इस उच्च स्तरीय पैनल के दो प्रमुख उद्देश्य हैं —

- ✓ पहला, दीर्घकालिक अवैध आव्रजन और घुसपैठ के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे असामान्य जनसांख्यिकीय बदलावों का एक व्यापक और अनुभवजन्य (empirical) आकलन करना।
- ✓ दूसरा, विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समुदायों में असामान्य जनसंख्या भिन्नताओं के आंतरिक पैटर्न का गणितीय विश्लेषण कर क्षेत्रीय जनसांख्यिकी को स्थिर करने के लिए एक संरचित और time-bound समाधान तैयार करना।

समिति की प्रमुख विशेषताएं

- **प्रधानमंत्री के आदेश से उत्पत्ति:** इस उच्च स्तरीय पैनल की संस्थागत रूपरेखा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से दिए गए स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषित आधिकारिक नीतिगत इरादे से उपजी है।
- **व्यापक जांच का दायरा:** समिति को field data एकत्र करने, border-fringe migration patterns को track करने और जिला एवं गांव स्तर तक ऐतिहासिक जनगणना भिन्नताओं की समीक्षा करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है।
- **समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण:** यह पैनल व्यापक राष्ट्रीय औसत के बजाय स्थानीय, तेज़ सामुदायिक बदलावों पर ध्यान केंद्रित करेगा — विशेषकर उन clusters की पहचान करने के लिए जहाँ undocumented जनसंख्या वृद्धि की दर असामान्य रूप से अधिक है।
- **Time-Bound कार्ययोजना:** समिति को एक कड़ी, पूर्व-निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना शोध पूरा करना होगा। इसका परिणाम एक blueprint report के रूप में सामने आएगा जिसमें नीतिगत बदलाव, border-control संबंधी सिफारिशें और data tracking पद्धतियां शामिल होंगी।

समिति का महत्व

- **राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा:** यह समिति अवैध सीमा पार करने की घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद करेगी जो मतदाता सूचियों, संसाधन वितरण और सीमावर्ती क्षेत्रों की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं।
- **जनजातीय पहचान की सुरक्षा:** समिति के निष्कर्ष झारखंड और पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों को जनसांख्यिकीय असंतुलन, भूमि अतिक्रमण और सांस्कृतिक क्षरण से बचाने में सहायक होंगे।

Prelims के लिए मुख्य तथ्य

- समिति का नाम Justice Prakash Prabhakar Naolekar Committee है।
- इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर हैं। यह गृह मंत्रालय (MHA) के अंतर्गत गठित की गई है।
- इसका Member Secretary Joint Secretary (Foreigners-I), MHA है।
- समिति का mandate अवैध आव्रजन और असामान्य जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच करना है। इसकी उत्पत्ति प्रधानमंत्री के Independence Day भाषण से हुई।

स्रोत: News on Air / गृह मंत्रालय, भारत सरकार

Question based on the Topic	
Mains question	**Prelims Question**
Question: Justice Naolekar Committee के उद्देश्यों, संरचना और कार्यक्षेत्र की विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जनजातीय समुदायों की सुरक्षा में इसके अपेक्षित योगदान का विश्लेषण कीजिए।	**5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:** 1. Justice Naolekar Committee का गठन केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा किया गया है। 2. इस समिति के अध्यक्ष Justice Prakash Prabhakar Naolekar हैं जो उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। 3. समिति का Member Secretary, Joint Secretary (Foreigners-I), MHA है। 4. इस समिति में Census Commissioner of India भी एक सदस्य हैं। **उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?** (a) केवल एक (b) केवल दो (c) केवल तीन (d) सभी चार **उत्तर: (c)** केवल तीन *(कथन 2 गलत है — Justice Naolekar सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के पूर्व न्यायाधीश हैं, न कि उच्च न्यायालय के। कथन 1, 3 और 4 सही हैं।)*

UPPCS 2026-27 (Foundation Course)

UPPCS 2026-27 (Foundation Course) Medium – Hindi Medium लाइव ऑनलाइन कक्षाएँ +...

1

₹15,000 ~~₹26,999~~ 45% off

View Details

UPSC/UPPCS GS Foundation Offline Batch 2026–27 | Prayagraj

UPSC और UPPCS की तैयारी अब होगी सही दिशा में – GS World IAS लेकर आया है General Studies...

₹55,999 ~~₹87,000~~ 36% off

View Details

UPSC IAS 2027 Foundation Course (Hindi)

Name – UPSC IAS 2027 Foundation Course 2026-27) Medium – Hindi Medium लाइव...

1

₹15,000 ~~₹26,999~~ 45% off

View Details

For Demo Classes, click on the image above.